जिम ट्रेनर ने फंदा लगाकर जान दी

जयपुर। अशोक नगर थाना क्षेत्र के सी-स्कीम में एक बीस वर्षीय जिम ट्रेनर ने कमरे में चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता तब चला,जब उसका रूम पार्टनर वापस लौटा और काफी देर तक दरवाजा नहीं खुलने पर मकान मालिक व पडौसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

एएसआई राम कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान मध्यप्रदेश के रतलाम निवासी हर्षित परमार (20) के रूप में हुई है। जो रमेश मार्ग सी-स्कीम स्थित एक कमरे में रूम पार्टनर के साथ किराए पर रहकर जिम ट्रेनिंग का काम करता था। एएसआई के अनुसार घटना के दौरान हर्षित मकान मालिक से टिफिन लेकर अपने कमरे में चला गया था। उसी दौरान उसका रूम पार्टनर किसी काम से अजमेर गया हुआ था। इस दौरान हर्षित ने कमरे में चुन्नी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। रूम पार्टनर के वापस लौटने पर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी देर तक आवाज लगाने और दरवाजा खटखटाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर उसने मकान मालिक और पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो हर्षित फंदे से लटका हुआ था।

लापरवाही से व्हील अलाइनमेंट करने पर सर्विस सेंटर पर हर्जानाा

जयपुर। जिला उपभोक्ता आयोग महानगर प्रथम ने व्हील अलाइमेंट के दौरान लापरवाही करने और ग्राहक की शिकायत को नजरअंदाज करने पर जयपुर टायर केयर पर 6000 रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही आयोग ने अलाइनमेंट और गाडी ठीक कराने के लिए खर्च किए 3901 रुपए भी ब्याज सहित परिवादी को लौटाने के आदेश दिए है। आयोग ने यह आदेश संदीप कुमार सैंगानी की ओर से दायर परिवाद पर सुनवाई करते हुए दिए। परिवाद में अधिवक्ता महेंद्र कुमार ने बताया कि परिवादी ने 4 जुलाई, 2023 को विपक्षी फर्म से अपनी कार का व्हील अलाइमेंट और बैलेंसिंग 859 रुपए खर्च कर कराई। इसके बाद गाडी चलाने के दौरान कार से अजीब से आवाज आने लगी। परिवादी ने इसकी शिकायत की तो सेंटर के संचालक ने बारिश का हवाला देकर उसे वापस भेज दिया। शिकायत बढ़ने पर परिवादी ने कार को अधिकृत सर्विस सेंटर पर चेक कराया। यहां टेक्नीशियन ने बताया कि व्हील अलाइनमेंट के दौरान पहिए के बोल्ट को इतना तेज कहा गया था कि इंजन, सस्पेंशन और टायर थामने वाले मेटल क्रॉस फ्रेम के दो बडे बोल्ट के माथे टूट गए थे। इस पर गाडी ठीक कराने के लिए अलग से 3901 रुपए खर्च करने पडे। दूसरी ओर सर्विस सेंटर की ओर से कहा गया कि गाडी के किसी बडे पत्थर से टकराने से बोल्ट टूटे होंगे।

ईवी वाहन के कीमती पार्ट्स चुराने वाला मिस्त्री गिरफ्तार

बगरू थानाधिकारी राजेंद्र कुमार गोदारा ने बताया कि परिवादी विकास कुमावत ने 15 जुलाई 2026 को बगरू थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 14 जुलाई की सुबह जब वह अपने वर्कशॉप पहुंचा तो वहां काम करने वाला मिस्त्री (डेंटर) मोहम्मद शहजाद उर्फ बब्बू गायब था। जांच करने पर वर्कशॉप से टाटा नेक्सॉन ईवी का चार्जर, इम्मोबिलाइजर, बैटरी फ्यूज, ईसीएम, बीसीएम फ्यूज बॉक्स, एयरबैग तथा कार की चाबी सहित करीब छह लाख रुपए का सामान गायब मिला।

मुख्यमंत्री ने लिया साइबर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया

शिकायत दर्ज होने से लेकर उसे संबंधित थाना एवं बैंक तक भेजने (डिस्पैच) की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और इसके लिए आवश्यक सभी सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वहीं बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने आर-4-सी (राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर) का निरीक्षण किया और साइबर अपराध रोकथाम के लिए विकसित तकनीकी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने साइबर क्राइम कंट्रोल रूम 1930 की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझा तथा स्वयं हेल्पलाइन पर आए एक पीड़ित की शिकायत सुनी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर साइबर क्राइम कंट्रोल रूम 1930 की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझा तथा स्वयं हेल्पलाइन पर आए पीड़ित की शिकायत भी सुनी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से शिकायत दर्ज होने से लेकर उसे संबंधित थाना एवं बैंक तक भेजने (डिस्पैच) की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के लाइव डैशबोर्ड का भी अवलोकन कर साइबर अपराधों की मॉनिटरिंग, शिकायतों के निस्तारण और तकनीकी निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह से मिलने पहुंची वसुंधरा राजे

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे शनिवार को अस्वस्थ चल रही 97 वर्षीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह की मिजाजपुर्सी करने उनके सी-स्कीम स्थित निवास पर पहुंची तो दोनों के बीच पुरानी स्मृतियों को लेकर लंबी चर्चा हुई।वहाँ उपस्थित लोगों के बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सिंह ने कहा कि वसुन्धरा का कार्यकाल नारी शक्ति को समर्पित रहा, जो कई मायनों में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इनके 2003 से 2008 के कार्यकाल में राजस्थान में तीन देवियां पहली बार प्रदेश के सर्वोच्च पदों पर आसीन थी। गत 8 दिसंबर 2003 को वसुन्धरा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनीं। मुझे भी इन्होंने 20 जनवरी 2004 को प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्रदान किया। उसी कालखंड में 8 नवंबर 2004 को राजस्थान में पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी।

त्रिवेणी संगम का ये दुर्लभ और सुखद संयोग था,जो अन्य किसी भी प्रदेश में आज तक देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसीलिए महिलाओं की तरक्की के लिए उस वक्त महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाने वाली दुनिया में पहली भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना, महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूटी-साइकिल योजना जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए,जो देश के लिए उदाहरण बने। राजे ने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने शनिवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह के सी-स्कीम स्थित आवास पर पहुंचकर कुशलक्षेम पूछी।

पुलिस कमिश्नर ने सुनी समस्याएं

जयपुर। आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को पुलिस थाना प्रताप नगर में जनसुनवाई की। इस दौरान सांगानेर सर्किल के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए परिवादियों की परिवेदनाएं सुनकर कई मामलों में मौके पर ही राहत दिलाई गई। साथ ही, शेष प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में प्रताप नगर, सांगानेर, मालपुरा गेट और रामनगरिया थाना क्षेत्रों से आए परिवादियों ने अपनी बात सीधे पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की। प्रत्येक परिवाद की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, संवेदनशील और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

आरएमएससीएल की दवा खरीद व गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली को भारत सरकार ने सराहा

जयपुर। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग के सचिव मनोज जोशी ने राजस्थान मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड (आरएमएससीएल) के माध्यम से रोगियों को सस्ती दर पर जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनाई जा रही खरीद प्रणाली की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि इसके माध्यम से रोगियों को गुणवत्ता युक्त दवाएं कम कीमत पर उपलब्ध हो रही हैं। इससे उन पर आर्थिक भार कम हुआ है। जोशी ने शनिवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास एवं आरएमएससीएल के अधिकारियों के साथ बैठक में दवाओं की खरीद, गुणवत्ता नियंत्रण एवं वितरण व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को सस्ती, सुलभ एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। जिला अस्पतालों से लेकर उप-स्वास्थ्य केंद्रों तक प्रत्येक स्तर पर आवश्यक दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आमजन को समय पर उपचार मिल सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि आरएमएससीएल के माध्यम से दवा वितरण केंद्रों पर बाजार भाव की तुलना में कम कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और प्रतिदिन 19 हजार केंद्रों पर लगभग 3.60 लाख लोगों को दवाई उपलब्ध करवाई जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रभावी प्रयासों का ही परिणाम है कि औषधि एवं टीका वितरण प्रबंधन प्रणाली के केंद्रीय डैशबोर्ड पर मई माह के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। आरएमएससीएल के प्रबंध निदेशक पुखराज सैन ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से दवाओं एवं चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया, भंडारण, बाजार दरों से तुलना तथा गुणवत्ता नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी दी।

प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखें : वी. श्रीनिवास

हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने

- 'लेबर रूम एवं ओटी के लिए जारी प्रोटोकॉल की पालना प्रतिदिन सुनिश्चित करें'
- 'मातृ मृत्यु ऑडिट कमेटी में विभागों के विशेषज्ञों को शामिल कर प्रति सप्ताह समीक्षा की जाए'

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को उपयुक्त अस्पताल (सीएचसी, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज) से मैप किया जाए तथा हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखें और आवश्यकता पड़ने पर डॉक्टर को तुरंत दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वी.श्रीनिवास शनिवार को स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएचओ, आरसीएचओ, पीएमओ, संयुक्त निदेशक-जोन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों व अस्पताल के अधीक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएचओ, आरसीएचओ, पीएमओ, संयुक्त निदेशक-जोन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों व अस्पताल के अधीक्षकों की बैठक ली।

उन्होंने कहा कि लेबर रूम एवं ओटी के लिए जारी प्रोटोकॉल की पालना प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिला से जुड़ी एएनएम प्रति 3 दिन बाद व्यक्तिगत सम्पर्क करेगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक मातृ मृत्यु की संस्थानिक समीक्षा स्तर पर एवं सामुदायिक स्तर पर रहे कारणों के साथ की जाए तथा अस्पतालों में बनाई गई मातृ मृत्यु ऑडिट कमेटी में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए प्रति सप्ताह समीक्षा की जाए। उन्होंने गर्भवती महिला का प्रसव पूर्व, दो बच्चों के अन्तर, एनीमिया तथा पूर्व प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गुड कम्युनिकेशन स्टेटेजी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन अस्पतालों में ओटी, आईसीयू, लेबर रूम आदि की क्रियाशीलता, उनमें उपचारित मरीजों की संख्या सहित अन्य जानकारी की प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज की मृत्यु चिकित्सकीय लापरवाही से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के न्यूट्रिशन एवं सुरक्षित प्रसव के संबंध में स्त्री रोग विशेषज्ञों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सर्जन के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए।

वी. श्रीनिवास ने बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, जनाना अस्पताल कोटा के विशेषज्ञों तथा झालावाड़ा जिले के सीएमएचओ से गर्भवती महिलाओं के उपचार में दी जा रही सुविधाओं, प्रोटोकॉल की पालना, ब्लड बैंक, आईसीयू, लेबर रूम, ओटी, प्रतिदिन होने वाले सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लक्षण सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव लिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रतिदिन होने वाले प्रसव, भर्ती गर्भवती महिलाओं की स्थिति, लेबर रूम, ओटी, बेड की उपलब्धता सहित अन्य जानकारियां स्टैण्डर्ड फॉर्मेट में मंगवाया जाना सुनिश्चित करावें।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि पूर्व में प्रोटोकॉल पालना से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं और विभाग द्वारा 15 जुलाई से 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक गर्भवती महिला को ट्रेक कर स्क्रीनिंग की जा रही है। एएनएम, सीएचओ एवं आशा वर्कर को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विभाग द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।बैठक में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा बाबूलाल गोयल, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी.शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर, आरएमएससीएल के कार्यकारी निदेशक जयसिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

पेपर लीक और ओएमआर घोटाला दबाने में जुटी सरकार : जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के नौजवान की सबसे बड़ी पीड़ा पेपर लीक और अटकी हुई भर्तियां हैं।

युवा बरसों तक किराए के कमरों में रातें काटते हैं, माता-पिता खेत गिरवी रखकर फीस भरते हैं, और परीक्षा से ठीक पहले पेपर बाजार में बिक जाता है। यह सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों की निर्मम हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपरलीक और ओएमआर घोटाला दबाने में जुटी है।

जूली ने यह बातें शनिवार को जयपुर में आयोजित "छात्र संविधान संवाद" कार्यक्रम में कही। जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2022 में देश का सबसे सख्त कानून बनाया था, जिसमें लंबी सजा और संपत्ति जब्ती तक का कड़ा प्रावधान है।

रीको ने औद्योगिक विकास के साथ-साथ श्रमिक आवास सुविधा का प्रावधान किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के विजन को आगे बढ़ाते हुए रीको ने अपनी फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में आंशिक संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ उद्योगों के लिए श्रमिक आवास सुविधा (वर्कर्स हाउसिंग फैसिलिटी) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित एवं स्थायी श्रमिक मिल सकें और श्रमिकों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवास फैक्ट्री के आसपास ही उपलब्ध हो सके। श्रमिक आवास सुविधा के लिये भूमि का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस आधार पर 30 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। पारस्परिक सहमति और निगम द्वारा उचित समझे जाने पर इस अवधि को 20 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।

प्रारंभिक बोली की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भूमि दर का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। किराया तिमाही आधार पर देय होगा तथा इसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अलावा लंबी अवधि के आवंटन के लिए 2 वर्ष मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

रीको द्वारा उद्यमियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। इसी वर्ष नीति के अंतर्गत प्लग एंड प्ले, स्पोर्ट्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन, नर्सरी, ग्रामीण हाट, मैरिज गार्डन तथा मसाला चौक जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। रीको के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए अब इस नीति में वर्कर्स हाउसिंग फैसिलिटी को भी शामिल किया गया है जिसके लिये रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड नियोजित किये जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉर्मिटरी आधारित रेंटल हाउसिंग विकसित करने की घोषणा की गई थी। यह योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित की जाएगी तथा इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का प्रावधान रहेगा।

रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि प्रशिक्षित एवं स्थायी श्रमिक किसी भी औद्योगिक विकास की मजबूत नींव होते हैं, जो निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास उपलब्ध होने से फैक्ट्रियों की उत्पादकता और श्रमिकों के स्थायित्व में वृद्धि होगी। उद्योगों को कुशल एवं नियमित कार्यबल उपलब्ध रहेगा तथा बड़े औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा।

- इस बदलाव के साथ श्रमिक आवास सुविधा के लिये भूमि का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया से लाइसेंस आधार पर 30 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। पारस्परिक सहमति और निगम द्वारा उचित समझे जाने पर इस अवधि को 20 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।

बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। विद्याधर नगर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश जुबैर उर्फ इरफान उर्फ भूरिया निवासी विद्याधर नगर को गिरफ्तार किया है।

कैंसर पीड़ित पत्नी के शिक्षक पति के तबादला आदेश पर रोक

जयपुर (कासं)। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने कैंसर की बीमारी से पीडित पत्नी के शिक्षक पति को राहत देते हुए उसके 270 किलोमीटर दूर किए तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अधिकरण ने कहा है कि अपीलार्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष इस संबंध में अपना अभ्यावेदन पेश करे और विभाग उस पर सहानुभूतिपूर्वक एक माह में निर्णय करे। अधिकरण ने यह आदेश हरिराम बैरवा की अपील पर दिए।अपील में बताया कि अपीलार्थी की पत्नी गंभीर रूप से स्तन कैंसर से पीडित है। इसके अलावा वह सेवानिवृत होने में भी दो साल से कम समय बचा है। पत्नी की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपीलार्थी पर है। इसके बावजूद भी विभाग ने गत दिनों उसका तबादला सवाई माधोपुर से धौलपुर कर दिया। ऐसे में तबादला आदेश को रद्द किया जाए। जिसके जवाब में शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि अपीलार्थी का तबादला प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग के 19 जून 2026 के आदेश के तहत प्रशासनिक जरूरतों के चलते किया गया है। किसी भी कर्मचारी को लंबे समय तक एक जगह कार्यरत नहीं रखा जा सकता।

'डेढ़ माह में 17 हजार प्रकरणों पर सुनवाई'

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण में दैनिक जनसुनवाई व्यवस्था के माध्यम से बीते डेढ़ माह में 17 हजार से अधिक प्रकरणों पर आमजन की सुनवाई करके मामलों का निस्तारण किया गया है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि लगभग 200 अधिकारी एवं कार्मिक प्रत्यक्ष रूप से आमजन की समस्याएँ सुन रहे हैं तथा उनका प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कर रहे हैं। परिणामस्वरूप डेढ़ माह की अवधि में 17 हजार से अधिक प्रकरणों की सुनवाई की जा चुकी है। साथ ही लगभग 500 प्रकरणों में ई-सुनवाई की गई। आंकड़ों के अनुसार जून माह में लगभग 10 हजार तथा जुलाई माह में अब तक लगभग 7 हजार प्रकरणों की सुनवाई की गई है। वहीं, 13 से 17 जुलाई के बीच केवल 5 दिनों में ही 2325 प्रकरणों पर सुनवाई कर आवश्यक कार्यवाही प्रारंभ की गई। जेडीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

वांगचुक को लेकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही कांग्रेस : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सोनम वांगचुक पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है। किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर इंतजार करना और उस पर राजनीति करना, कांग्रेस का यह रवैया सही नहीं है। सरकार की पहली प्राथमिकता किसी भी नागरिक का जीवन बचाने की होती है, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाना पूरी तरह उचित निर्णय है। किसी की जान पर राजनीति करना विकृत मानसिकता का परिचायक है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि वांगचुक का स्वास्थ्य और बिगड़ जाए, ताकि बाद में सरकार को घेरकर राजनीतिक लाभ लिया जा सके। उन्हें आमरण अनशन जैसा कदम उठाने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी भी मांग पर चर्चा और बहस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है।

कानोता में 6 बीघा भूमि पर बसाई जा रही दो अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने कानोता क्षेत्र में करीब 6 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही दो अवैध कॉलोनियों को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त किया। उप महानिरीक्षक आनन्द शर्मा ने बताया कि जोन-24 के क्षेत्राधिकार में ग्राम कानोता, आनन्द कॉलेज के पास दुधावाला रोड पर करीब 2 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर जेडीए की बिना स्वीकृति एवं बिना भू-रूपांतरण कर भूमि को समतल कर बनाई गई।

सार-समाचार

50 वर्ष पुराने स्नातकों का पुनर्मिलन

जयपुर। महाराजा कॉलेज के 50 वर्ष पुराने स्नातकों का पुनर्मिलन समारोह शनिवार को जयपुर में आयोजित हुआ। आधी सदी यानि करीब (50 साल) बाद पूर्व छात्र शनिवार को रोड नंबर 9, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित विश्वकर्मा रिक्रिएशन क्लब में इकट्ठे हुए। आयोजन समिति के सदस्य प्रमोद खंडेलवाल, इकबाल सिंह और नर सिंह स्वर्णकार ने बताया कि इस विशेष दिन की शुरुआत दोपहर के स्नेहभोज के साथ हुई। इसके पश्चात, पुरानी यादों को ताजा करने के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित हुए। समारोह में देश-विदेश से कॉलेज के पुराने सहपाठी शामिल होकर अपने छात्र जीवन के अनुभवों और सुनहरे पलों को याद किया। इस मौके पर पूर्व महापौर अशोक परनामी, न्यायमूर्ति बनवारी लाल शर्मा, एन.के.शर्मा, अध्यक्ष, राजस्थान नियोक्ता संघ और जर्मनी से जुल्फिकार अहमद ने समारोह में भाग लिया। हरि मोहन शर्मा को सुंदर इवेंट मैनेजमेंट का श्रेय दिया गया।

पिंक ड्राइव से दिया स्वच्छता का संदेश

जयपुर। समुदाय आधारित नागरिक पहल जयपुर-बाय-जयपुराइट्स की ओर से सुबह पिंक ड्राइव 2.0 का आयोजन किया गया। यह 'प्लॉगिंग एवं स्वच्छता अभियान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सिंधी कैंप के प्लेटफॉर्म-1 से शुरू हुआ। 7 जून को आयोजित पहली पिंक ड्राइव की सफलता के बाद आयोजित इस दूसरे अभियान की थीम "स्वच्छ शहर, बेहतर कल" रही। अभियान में 6 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के करीब 50 स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभी ने सिंधी कैंप और आसपास के क्षेत्रों में फैले कचरे को एकत्रित कर स्वच्छता का संदेश दिया और नागरिक जिम्मेदारी निभाने का संकल्प लिया। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और जयपुर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना था। अभियान के दौरान सभी स्वयंसेवकों को सुरक्षा जैकेट, डिस्पोजेबल मास्क और दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले दस्ताने उपलब्ध कराए गए, ताकि वे सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से स्वच्छता अभियान में भाग ले सकें। इस अभियान को सिंधी कैंप बस स्टैंड के मुख्य प्रबंधक राकेश राय तथा सिंधी कैंप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी पूरा सहयोग मिला, जिनके समर्थन से यह स्वच्छता अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।

संस्कृत विवि. में सिंडिकेट की बैठक

जयपुर। जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद (सिंडिकेट) की बैठक शनिवार को कुलपति प्रो. मदनमोहन झा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में शिक्षकों की पदोन्नति, आठवें दीक्षांत समारोह तथा नवीन पाठ्यक्रमों सहित अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। कुलसचिव डॉ. गुंजन सोनी ने बताया कि राज्यपाल की अध्यक्षता में 7 सितंबर को होने वाले विश्वविद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में दिए जाने वाले स्वर्ण पदकों एवं डिग्रियों के प्रस्ताव को कार्य परिषद ने अनुमोदित किया। बैठक में कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के सह-आचार्य डॉ. राजधर मिश्र, डॉ. विनोद कुमार शर्मा और डॉ. माताप्रसाद शर्मा को प्रोफेसर पद पर पदोन्नत करने की स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय परिसर तथा प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों में मौजूदा शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाने वाले नवीन पाठ्यक्रमों को भी मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में विश्वविद्यालय में स्थापित आठ शास्त्रीय पीठों पर पीठाध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर भी कार्यपरिषद ने सहमति व्यक्त की। बैठक में राज्यपाल प्रतिनिधि प्रो. यशवीर सिंह, शिक्षक प्रतिनिधि डॉ. स्नेहलता शर्मा, संकायाध्यक्ष सदस्य प्रो. शालिनी सक्सेना तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि प्रो. राकेश जोशी सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

वार्ष्णेय सुर संगम 26 जुलाई को

जयपुर। राजस्थान वैश्य वार्ष्णेय सभा जयपुर के तत्वावधान में 26 जुलाई को श्री वार्ष्णेय वैश्य सदन पालड़ी मीणा में दोपहर 3 बजे से सांस्कृतिक संगीत कार्यक्रम वार्ष्णेय सुर संगम का आयोजन किया जाएगा। आयोजन समिति के बृजेश कुमार एवं राजेश गुप्ता ने बताया कि इस कार्यक्रम में राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों से वार्ष्णेय समाज के 50 से अधिक प्रतिभागी फ़िल्मी गीत, भजन, ग़ज़ल एवं शास्त्रीय संगीत की एकल प्रस्तुतियाँ देंगे।